



RAJIV GANDHI NATIONAL UNIVERSITY OF LAW, PUNJAB
(Established under Punjab Act No. 12 of 2006)
(Accredited with 'A' Grade by NAAC)

RGNU/PRO/2023/172

Date: 04-11-2023

**RGNU organises National Seminar on 'Fostering Gender Justice: An
Assessment of Challenges and Strategies'
3rd - 4th November 2023**

The Rajiv Gandhi National University of Law, Punjab organised a two-day national seminar on 'Fostering Gender Justice: An Assessment of Challenges and Opportunities' from 3rd November to 4th November, 2023. The national seminar was inaugurated on 3rd November by Prof. (Dr.) Nishtha Jaswal, Vice-Chancellor, Himachal Pradesh National Law University, Shimla along with Prof. (Dr.) Anand Pawar, Officiating Vice-Chancellor, RGNUL, Punjab, Prof. (Dr.) Sharanjit, Convenor and Dr. Manoj Kumar Sharma, Organising Secretary. Dr. Manoj Kumar Sharma introduced the theme of the Seminar. He highlighted the fact that despite plethora of provisions in the Constitution of India and host of laws enacted to achieve gender equity, India ranks 127 out of 146 countries in gender parity as per the Gender Gap Report, 2023 of the World Economic Forum. Prof. (Dr.) Anand Pawar discussed various legal and constitutional provisions enacted by the Government of India and State governments for achieving gender equality. He also highlighted various policy measures and legislative measures including Nari Shakti Vandan Adhiniyam enacted for ensuring gender justice. Prof. (Dr.) Nishtha Jaswal highlighted the position of women in ancient Indian society referring to ancient scriptures and Vedas. She discussed and summed up various judicial pronouncements relating to gender justice of the Supreme Court of India. She also emphasised on the socio-economic position of the third gender in the society and the need for taking immediate measures for promoting their welfare and their inclusion in the mainstream. She further discussed issues relating to the misuse of various laws enacted for the protection and welfare of women. She appealed to the students to become harbingers of change in the society. The inaugural event ended with a vote of thanks delivered by Prof. (Dr.) Sharanjit. She stressed upon the need for effective implementation of the laws for the welfare of women.

The two-day seminar witnessed submissions and presentations on aspects relating to Legal Pluralism and Gender Justice; Constitutionalism and Gender Justice; Gender and Human Rights; Globalisation and Gender Justice, among others. Around 64 papers were presented by the participants from across the country in eight technical sessions of the conference.


Public Relation Officer


Registrar

Danik Bhaskar (06)

November 05, 2023

राजीव गांधी लॉ यूनिवर्सिटी में लैंगिक न्याय को बढ़ावा विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी करवाई

एचपीयू के वीसी ने किया उद्घाटन, चुनौतियों और रणनीतियों का किया आंकलन

भास्कर न्यूज। पटियाला

राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ने लैंगिक न्याय को बढ़ावा विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। इसमें विषय पर चुनौतियों और अवसरों का आंकलन भी किया गया। सेमिनार का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर (डॉ.) निष्ठा जसवाल ने किया। प्रोफेसर (डॉ.) आनंद पवार, प्रो. (डॉ.) शरणजीत, डॉ. मनोज कुमार शर्मा की उपस्थिति में डॉ. मनोज कुमार शर्मा ने संगोष्ठी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि भारत के संविधान में ढेर सारे प्रावधान और इसे हासिल करने के लिए बनाए गए कई कानूनों के बावजूद लैंगिक समानता, लैंगिक अंतर के अनुसार भारत लैंगिक समानता में 146 देशों में से 127वें स्थान पर है। विश्व आर्थिक मंच की



पटियाला की राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ने 'लैंगिक न्याय को बढ़ावा' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में देश भर से विशेषज्ञ।

रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रो. (डॉ.) आनंद पवार ने कहा कि भारत और राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित कानूनी और संवैधानिक प्रावधान लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए विभिन्न नीतिगत उपायों पर प्रकाश डाला। लिंग सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम

सहित विधायी उपाय लागू किए जाने पर जोर दिया। प्रो. (डॉ.) निष्ठा जसवाल ने प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। विशेषज्ञों ने कहा कि समाज प्राचीन ग्रंथों और वेदों का हवाला दे रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की लैंगिक न्याय से

संबंधित न्यायिक घोषणाओं के बारे में भी सेमिनार में उपस्थित लोगों को विस्तार से जानकारी दी गई। समाज में तीसरे लिंग की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और आवश्यकता पर जोर दिया गया। उनके कल्याण को बढ़ावा देने और उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने के लिए तत्काल उपाय करने को कहा गया। उन्होंने सुरक्षा के लिए बनाए गए विभिन्न कानूनों के दुरुपयोग से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की और महिलाओं के कल्याण पर जोर दिया। विशेषज्ञों ने छात्रों से बदलाव का अग्रदूत बनने की अपील की। प्रोफेसर (डॉ.) शरणजीत ने धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सेमिनार को समाप्त करने से पहले अतिथियों का धन्यवाद किया। इससे पूर्व उन्होंने अपने संबोधन में लोगों के कल्याण के लिए कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया। गौर हो कि इस सेमिनार में देश भर से आए विशेषज्ञों ने 64 पेपर प्रस्तुत किए।

Punjabi Tribune (11)

November 05, 2023

ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਅੰਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ

ਤੀਜੇ ਜੈਡਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕ

ਪਟਿਆਲਾ, 4 ਨਵੰਬਰ

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ਵਿਚ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 146 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 127ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਜੈਡਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 'ਫਾਸਟਰਿੰਗ ਜੈਡਰ

ਜਸਟਿਸ: ਐਨ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਚੈਲੇਂਜਿਜ਼ ਐਂਡ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਨਿਸ਼ਠਾ ਜਸਵਾਲ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਅਨੰਦ ਪਵਾਰ, ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨੋਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪ੍ਰੋ. ਅਨੰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।